यूनियन बजट (2018-19) पर **दिनांक: 01.02.2018**

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की प्रतिक्रियाए

माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट (2018-19) पर मर्चेंट्स चैम्बर ने अपनी निम्नलिखित सकारात्मक प्रतिक्रियाए दी:

- विकास, रोजगार को गति देने वाला है तथा बजट को देश की जनता के बड़े भाग की तरक्की के द्रष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है जिसके विकास का फायदा सभी को होगा।
- 99% उद्योगों को करों की कमी का फायदा दिया गया है जिससे निवश की राशि को बढ़ावा मिलेगा।
- आयात पर कर बढ़ाकर मेक इन इंडिया को बढावा दिया गया है।
- 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन तथा 8 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।
- बजट में 27 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रावधान किया गया है।
- बजट को गाँव, गरीब व् किसान का बजट कहा जा सकता है।
- पशुपालक, मछलीपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- उक्त बजट को लोकलुभावन नहीं कहा जा सकता है बल्कि यह विकास व् वृद्धि-दर के बढ़ावे का बजट है।
- उक्त बजट कृषि बजट भी कहा जा सकता है क्योकि इसकी अधिकतर प्रावधान कृषि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गए है।
- नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत प्रति परिवार रुपया 5 लाख वार्षिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति का प्रावधान है जो कि 10 करोड़ परिवारों को दी जायेगी।
- बजट में वेतनभोगी लोगों को कर के स्लैब में थोड़ी राहत दी गयी है।
- बजट में पेट्रोल व् डीजल की एक्साईज ड्यूटी में रुपया 2/- लीटर की कमी की गयी है।

उपरोक्तलिखित बिन्दुओं पर चैम्बर के अध्यक्ष श्री बी.के. लाहोटी, उपाध्यक्ष-श्री बी.एम. गर्ग, फिस्कल कमिटी के चेयरमेन श्री मुकुल टंडन, श्री सुधीन्द्र जैन, श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव, श्री अतुल मेहरोत्रा, श्री संतोष गुप्ता, श्री अनिल अग्रवाल, आदेश टंडन, श्री आर.आर. जैन, श्री सुशील शर्मा, श्री शेष नारायण त्रिवदी, श्री ए.के. सिन्हा, श्री एम.एन. मोदी।

सधन्यवाद